FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 9.8.2024
Page No. 22, Size:(7.92)cms X (15.65)cms.

Electric vehicles and hybrids must coexist

RAJAN WADHERA

IN RECENT DAYS there has been an intense debate among leading Indian car manufacturers on the recent UP Government's EV policy on whether to incentivise Hybrids or not. Having spent more than four decades in the Auto Industry, developing products, working on clean technologies, running a company and heading a research organisation, a fair conclusion can be drawn that nothing is above the national interest, and it can be said that the whole debate is avoidable in the larger national interest.

Both sides will unanimously agree that they want incentives for Battery Electric Vehicles (BEVs). When it comes to Hybrids, the ones who have Hybrid models want incentives, while the ones who do not have Hybrid models in the market want the UP Government to withdraw incentives on Hybrids.

The question arises what is in the national interest for which the whole EV policy has been framed? The national interest lies in reducing crude oil import bills, as outlined by Prime Minister, Narendra Modi, time and again and in reducing the country's carbon emissions.

It is perfectly possible and legitimate that different car manufacturers adopt different pathways for achieving these two objectives. It is not necessary that every manufacturer find every technology suitable as per their market or product strategy.

In this war of words, some manufacturers have claimed that giving incentives to Hybrids will affect their EV plans. That is not true. EVs have their hurdles to adoption like charging infrastructure, upfront cost, anxiety on resale value, financing, safety-related concerns, etc. In fact, as per a recent research survey, more than 50% of the existing EV customers want to switch back to ICE vehicles. This indicates that there are gaps within the total EV offering to the customer that need to be plugged in. Manufacturers need to work both individually and jointly with all stakeholders to address these hurdles.

Large-scale adoption of strong hybrids in India would lead to a meaningful reduction in the import bill, cutting down carbon emissions and making it an environmentally-friendly move

Incidentally, India is not alone in this challenge, but the hurdles are similar all over the world. But it is entirely incorrect to say that the growth of EVs is restricted because of Hybrids and it is time to understand that technology needs to come into play for the transition between ICE vehicles and EVs and currently nothing seems better than the hybrids.

Both EVs and hybrids have achieved about 2% sales penetration each currently, which adds up to 4%.

As a country, we want this 4% to grow at the expense of the balance of 96%. Hybrids reduce petrol consumption and CO_2 emissions by a good 30-40%.

Since they do not need charging infrastructure, they have the potential to proliferate and deliver results fast. Considering that EVs may not grow beyond 20-30% sales penetration even in the next 10 years, there is absolutely no logic in blocking or holding back Hybrid technology. Both these technologies complement each other.

In fact, many components/modules are the same in EVs and Hybrids like the motor, the power electronics, etc. The combined volumes of both EVs and Hybrids will give economies of scale and scope to make manufacturing of these components/modules in India viable.

Various credible industry, academia, and government bodies have independently studied the benefits of Hybrids and recommended incentivisation of this technology. Even globally, in many countries including China, the US, the UK, and France, Hybrid penetration is increasing and most of the countries are incentivising this technology through lower taxation to encourage mass adoption.

Therefore, in my opinion, large-scale adoption of strong hybrids in India would lead to a meaningful reduction in the import bill, cutting down carbon emissions and making it an environmentally-friendly move.

Hybrids will not only complement BEVs but also derisk our decarbonisation roadmap.

In fact, both Hybrids and BEVs combined could replace the pure petrol / diesel engine vehicles, which is in any case required to meet these objectives.

The need of the hour is to rise above this debate and work towards developing and offering these technologies, increase customer confidence, and make India a manufacturing hub for all electrified technologies.

(The writer is former SIAM president, former president Mahindra & Mahindra (Automotive Sector) and former President ARAI. Views are personal)

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 9.8.2024
Page No. 11, Size:(17.46)cms X (19.79)cms.

Oil India posts ₹14.67 bn net profit in June qtr

Informist
NEW DELHI

Upstream crude oil and natural gas explorer and producer Oil India Ltd on Thursday reported a 27.7% sequential fall in its net profit to 14.67 bln rupees in the quarter ended June as the crude oil segment recorded stagnant revenue growth and a decline in operating profit. A fall in other income, and rise in tax expenses also contributed to the sequential fall in its net profit. The company's net profit also missed the Street's estimate of 17.32 bln rupees.

The topline was up by just 1.4% on quarter to 58.40 bln rupees, mainly due to a sluggish 0.8% growth in revenue from crude oil at 42.08 bln rupees. Revenue from pipeline transportation was down sharply by 25% on quarter to 1.25 bln rupees in Apr-Jun.

Aiding the revenue growth of Oil India was a 6.5% sequential increase in revenue from natural gas to 14.22 bln rupees. The reported revenue was above analysts' average estimate of 57.93 bln rupees.

The company's earnings before interest and tax, or EBIT, fell 22% sequentially to 19.75 bln rupees in Apr-Jun as the crude oil segment's EBIT declined 8.2% to 16.03 bln rupees.

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Ghaziabad, 9.8.2024
Page No. 3, Size:(18.77)cms X (13.37)cms.

ठगों के निशाने पर 20 लाख पीएनजी उपभोक्ता

हसीन शाह • जागरण

साहिबाबाद : दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपभोक्ता ठगों के निशाने पर हैं। ठग उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन काटने का मैसेज भेजकर ठगी कर रहे हैं। ऐसे में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) उपभोक्ताओं को अलर्ट करने के लिए ई-मेल भेजनी शुरू कर दिया है। जिससे लोग ठगों से बच सकें।

पीएनजी के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 20 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन हैं। पिछले दो माह से उपभोक्ताओं के पास गैस कनेक्शन कटने के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में कनेक्शन काटने का समय लिखा जाता है। मैसेज देखते ही उपभोक्ता को खाना बनाने की चिंता सताने लगती है। मैसेज में लिखा होता था- ' प्रिय उपभोक्ता आपका इंद्रप्रस्थ गैस कनेक्शन आज रात 09:30 बजे काट दिया जाएगा। आपने पिछले माह का बिल अपडेट नहीं किया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर काल करें।' इस मैसेज में नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। जैसे ही उपभोक्ता उस नंबर फोन करता और उनके दिए गए लिंक पर क्लिक करता है तो खाते से रकम साफ हो जाती है। इस तरह के मैसेज आने पर उपभोक्ता आइजीएल कंपनी के अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। आइजीएल के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला है कि यह फर्जी मैसेज हैं। आइजीएल के पास काफी संख्या में इस तरह की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई इस तरह का मैसेज आता है तो वह सतर्क हो जाएं।

आइजीएल गैस कनेक्शन • जागरण

केस स्टडी

1 - वसुंधरा के परिवहन अपार्टमेंट के नीरज त्यागी ने बताया कि उनके मोबाइल पर पीएनजी कनेक्शन कटने का मैसेज आया था। जब उन्होंने आइजीएल के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो उन्हें इस फर्जी मैसेज के बारे में पता चला।

2- वसुंधरा की पूनम बंसल ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन काटने का उनके पास मैसेज आया था। फर्जी नंबर पर पैसे डालने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर की थी।

300 से ज्यादा लोगों के पास फर्जी मैसेज प्रतिदिन आ रहे।

50 प्रतिशत से अधिक लोगों को अलर्ट करने को आइजीएल ने भेजा ई-मेल।

10 अंकों का बीपी नंबर दर्ज कर चेक कर सकते हैं उपभोक्ता।

उपभोक्ताओं के पास काल भी आ रहे

मैसेज के अलावा ग्राहकों के पास कॉल भी आ रहे हैं। ठग खुद को आइजीएल का अधिकारी बताता है। वह जल्द-से-जल्द बिल न जमा करने पर गैस कनेक्शन काटने की चेतावनी देता है। इसके बाद ठग वाट्सएप पर क्यूआर कोड भेज देता है। आइजीएल के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक करने का निर्णय लिया है। आइजीएल की ओर से उपभोक्ताओं को ई-मेल कर अलर्ट किया जा है।

सभी मैसेज में होता है एक ही समय

जिन उपभोक्ताओं के पास मैसेज आता है उन सभी में एक जैसे ही मैसेज हैं। टाइम भी एक ही लिखा होता है। वहीं ठगों के पास उपभोक्ताओं का नंबर कैसे पहुंचा। इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है।

इन बातों का रखे ध्यान

- आइजीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर 10 अंकों का बीपी नंबर दर्ज कर चेक कर सकते हैं।
- कोई लिंक आए तो उस पर क्लिक न करें
- क्यूआर कोड को स्कैन बिल्कुल न करें
- गैस कनेक्शन काटने के मैसेज अनदेखा कर दें
- मैसेज आने पर कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर काल करें।
- हेल्पलाइन नंबर भी आधिकारिक वेबसाइट चेक करके लें।
- बैंक, क्रेडिड व डेबिट कार्ड आदि की जानकारी साझा न करें।
- एनी डेस्क या टीम व्यूअर्स एप मोबाइल में इंस्टाल न करें।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), NOIDA, 9.8.2024
Page No. 4, Size:(4.26)cms X (14.98)cms.

ठगों के निशाने पर 20 लाख पीएनजी उपभोक्ता

जासं, साहिबाबाद : दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपभोक्ता ठगों के निशाने पर हैं। ठग उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन काटने का मैसेज भेजकर ठगी कर रहे हैं। ऐसे में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) उपभोक्ताओं को अलर्ट करने के लिए ई-मेल भेजनी शुरू कर दिया है। जिससे लोग ठगों से बच सकें। पीएनजी के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 20 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन हैं। पिछले दो माह से उपभोक्ताओं के पास गैस कनेक्शन कटने के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में कनेक्शन काटने का समय लिखा जाता है।

इस मैसेज में नीचे मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। जैसे ही उपभोक्ता उस नंबर फोन करता और उनके दिए गए लिंक पर क्लिक करता है तो खाते से रकम साफ हो जाती है। शिकायत पर आइजीएल के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला है कि यह फर्जी मैसेज हैं। आइजीएल के पास काफी संख्या में इस तरह की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई इस तरह का मैसेज आता है तो वह सतर्क हो जाए। यह मैसेज आइजीएल से नहीं भेजे जा रहे हैं।

ECONOMIC TIMES, Delhi, 8.8.2024
Page No. 1, Size:(20.12)cms X (16.77)cms.

SCN SERVED FOR 2017-23

Mahindra Group Cos Run into 'Brand' Tax

Get GST notice for using parent name

Sugata Ghosh & Rashmi Rajput

Mumbai: In a move that could open a Pandora's box and spark an outcry from Corporate India, Mahindra & Mahindra has been served a notice from the office of the goods and services tax (GST) for the use of the 'Mahindra' brand name by various group companies.

The show cause notice has questioned why M&M should not pay GST for the service given by the parent to the group companies by letting them use the flagship brand and logo. The notice relates to 2017-23. A Mahindra spokesperson declined to comment to **ET** on the communication from the indirect tax department.

Different Interpretations ▸▸ 17

ECONOMIC TIMES, Delhi, 8.8.2024
Page No. 1, Size:(20.12)cms X (16.77)cms.

Different Interpretations

▸▸ From Page 1

Tax officials believe GST should be imposed on the royalty or fee that group entities are supposed to pay to the parent company, even as corporate circles and senior tax practitioners think it's an absurd demand. "How do you ascribe a value to a brand and determine the fee which subsidiaries and associates in different businesses would have to pay?" said a tax professional.

However, if the GST department sticks to its stand, multiple business houses would be exposed to such notices and subsequent tax claims.

GST is paid by consumers and remitted to the government by the businesses selling the goods or services. For instance, if the royalty amount is fixed at Rs 10 crore, the applicable GST on it, at 18%, would be Rs 1.8 crore. So, the parent company would receive Rs 11.8 crore from the group company and pay Rs 1.8 crore to the government.

It's unclear at this stage whether the department is testing the waters as GST, administered under a comparatively recent statute, lends itself to different interpretations. Under the GST law, tax applies in 'related party transactions' even if no consideration is paid. A few months ago, multiple builders in Mumbai were sent notices for lending their brand and trade names to subsidiaries, joint ventures and special purpose vehicles (SPVs) carrying out the projects.

In real estate and infrastructure development, each project is typically organised under a separate entity or SPV. Such vehicles, controlled by the main company, carry out construction, fundraising and property sale under the parent's umbrella brand.

Compared to the real estate business, where different SPVs carry out the same activity, member companies of a diversified group are engaged in different businesses.

Unlike 'corporate guarantees,' there are no specified rules for brand fee. On guarantees — often extended by the parent to help group companies obtain higher credit rating and raise money at a cheaper rate — the tax is levied at the rate of 18% on 1% of the total guarantee amount. So, if the size of a corporate guarantee is Rs 100 crore, the parent company will have to shell out Rs 18 lakh as GST.